

## नरियात तत्परता सूचकांक 2021: नीतिआयोग

### प्रलिस के ललल:

नरियात तत्परता सूचकांक, नीतिआयोग, सकल घरेलू उत्पाद के घटक ।

### मेन्स के ललल:

सरकारी नीतलरल और हसूतकषेप, संसाधन जुटाना, आरूथकल वकलस दर में तेजू से वृद्धल हासलल करने के ललल नरियात, नरियात प्रोत्साहन के मुदूँ हेतु चुनूतलरल और आगे की राह ।

## चरूा में कूरूँ?

नीतिआयोग दूवारा जारी नरियात तत्परता सूचकांक (Export Preparedness Index- EPI), 2021 के अनुसार, गुजरात को लगातार दूसरे वरूष नरियात तैयारलरल के मामले में भारत का शीरूष राज्य नामलल कलल गया है ।

- सूचकांक में महाराषूटर, कर्नाटक, तमललनाडु कूरूमशः दूसरे, तीसरे और चूथे स्थान पर है, कूरूँक उचूच औदूयोगकल गतवलधलरल के साथ समुदर तटीय बंदरगाहूँ वाले राज्य भारत के अधकलंश नरियात के ललल जूमलमेदार है ।

## नरियात तत्परता सूचकांक (EPI):

- चुनूतलरल और अवसरूँ की पहचान करना, सरकारी नीतलरल की प्रभावशीलता को बढ़ाना तथा नरियात के ललल एक सुवलधलजनक नललमक ढूँचे को प्रोत्साहलल करना ।
- सूचकांक में 4 सूतूँ, 11 उप सूतूँ और 60 संकेतक शामिल है तथा इसमें 28 राज्य एवं 8 केंदरशासलल प्रदेश शामिल है ।
- चार सूतूँ:
  - नीतलः नरियात और आयात के ललल रणनीतकल दशल प्रदान करने वाली एक वूयापक वूयापार नीतल ।
  - बज़लनेस इकोसलसूतमः एक कुशल बज़लनेस इकोसलसूतम जो राजूरूँ को नवलश आकूरूषलल करने और सूटारूट-अप शुरू करने हेतु वूयकूतलरल के ललल एक सकूषम बुनयलदी ढूँचा बनाने में मदद करता है ।
  - नरियात पारसूथलतलकल तंतरूः कारोबारी माहूँल का आकलन करना, जो नरियात के ललल वशलषलत हो ।
  - नरियात प्रदरूशनः यह एकमातर आउटपूट-आधारलल पैरामीटर है जो राजूरूँ और केंदरशासलल प्रदेशूँ के नरियात गतवलधलरल की जूँच करता है ।
- गूयारह उप-सूतूँ:
  - सूचकांक में 11 उप-सूतूँ- नरियात प्रोत्साहन नीतलः संसूथागत ढूँचा, वूयापारकल वातावरण, आधारभूत संरचना, परवलहन कनेकूटवललल, वतलत तक पहुँच, नरियात बुनयलदी ढूँचा, वूयापार समरूथन अनुसंधान एवं वकलस अवसंरचना नरियात ववलधलकरण और वकलस अभवलनलयास के आधार पर शूरूणी तैयार की गई है ।
  - सूचकांक की वशलषतलएँः ईपीआई उप-राषूटरीय सूतर (राजूरूँ और केंदरशासलल प्रदेशूँ) पर नरियात को बढ़ावा देने के ललल महतूतूवपूरूण मुखूय कूषेतरूँ की पहचान करने हेतु डेटा-संचालन का प्रयास है ।
    - यह प्रतूथेक राज्य और केंदरशासलल प्रदेशूँ दूवारा कलल गए वभलनलनलन योूगदानूँ की जूँच कर भारत की नरियात कूषमता पर प्रकाश डालता है ।
  - भारतीय राजूरूँ/संघ राज्य कूषेतरूँ का प्रदरूशनः

Himalayan		
State	Score	Rank
Uttarakhand	40.79	1
Himachal Pradesh	40.43	2
Tripura	27.46	3
Sikkim	27.41	4
Manipur	15.78	5

Coastal		
State	Score	Rank
Gujarat	78.86	1
Maharashtra	77.14	2
Karnataka	61.72	3
Tamil Nadu	56.84	4
Andhra Pradesh	50.39	5

Landlocked		
State	Score	Rank
Haryana	53.20	1
Uttar Pradesh	51.09	2
Madhya Pradesh	51.03	3
Punjab	50.99	4
Telangana	47.92	5

UT/City States		
State	Score	Rank
Delhi	43.66	1
Goa	41.95	2
Jammu and Kashmir	30.06	3
Chandigarh	28.41	4
Puducherry	22.19	5

## नरियात तत्परता सूचकांक (EPI) का महत्त्व:

- **राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नरियात प्रदर्शन की जाँच:** इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नरियात प्रदर्शन एवं नरियात हेतु तैयारी की जाँच करना है।
  - सूचकांक के पीछे नहिती वचिर इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को रैंकिंग प्रदान करने हेतु एक बेंचमार्क नरिमति करना है ताकि उनहें इस कषेत्र में एक अनुकूल नरियात वातावरण को बढावा देने में मदद मलि सके।
- **नरियात में आने वाली बाधाओं की पहचान करने में सहायक:** सूचकांक नीति नरिमाताओं और नरियातकों को गति प्रदान करने, बाधाओं की पहचान करने तथा राज्य हेतु एक व्यवहार्य नरियात की रणनीति बनाने और इसकी जाँच करने हेतु एक आवश्यक उपकरण है।
- **राज्य सरकार के लिये पथ-प्रदर्शक:** सूचकांक राज्य सरकारों के लिये नरियात प्रोत्साहन के संबंध में कषेत्रीय प्रदर्शन को चहिनति करने हेतु एक सहायक मार्गदर्शिका होगी और इस प्रकार नरियात में सुधार एवं वृद्धि करने के बारे में महत्त्वपूर्ण नीतितगत अंतरदृष्टि प्रदान करेगा।
- **राज्यों के मध्य प्रतसिपर्द्धा को बढावा:** इसका प्राथमिक लक्ष्य सभी भारतीय राज्यों ('तटीय', 'लैंडलॉकड', 'हमिलयी' और 'यूटी/सिटी-स्टेट्स') के बीच अनुकूल नरियात-संवर्द्धन नीतियों को लागू कर प्रतसिपर्द्धा को बढाना, नयिमों को आसान बनाना, उप-राष्ट्रीय नरियात को बढावा देने व नरियात के लिये आवश्यक बुनयादी ढाँचे का नरिमाण तथा नरियात प्रतसिपर्द्धात्मकता में सुधार हेतु रणनीतिक सफिरशिं प्रदान करना है।

## भारतीय नरियात के लिये चुनौतियाँ:

- EPI भारत के नरियात प्रोत्साहन प्रयासों के लिये तीन प्रमुख चुनौतियों की पहचान करता है।
  - नरियात बुनयादी ढाँचे में भनिनता और अंतर-कषेत्रीय वभिदिता।
  - राज्यों में कमज़ोर व्यापार समर्थन और वकिस अभविन्यास।
  - महत्त्वपूर्ण नरियात को बढावा देने हेतु अनुसंधान एवं वकिस बुनयादी ढाँचे की कमी।

## भारतीय नरियात के संदर्भ में EPI:

- **नरियात उनमुख भारतीय अर्थव्यवस्था:**
  - जीडीपी = नजिी खपत + सकल नविश + सरकारी नविश + सरकारी खर्च + नरियात-आयात।
  - इस प्रकार नरियात जीडीपी मूल्यों को बढाने के लिये एक आवश्यक घटक है।
  - नरियात भारत के आर्थिक वकिस का एक अवभाज्य घटक है क्योंकि पिछले एक दशक से नरियात भारत के सकल घरेलू उत्पाद में औसतन लगभग 20% का योगदान कर रहा है।
- **कोवडि-19 से रकिवरी:** कोवडि-19 महामारी ने मौजूदा आर्थिक ढाँचे को उलट दिया और वैश्विक व्यापार एवं अर्थव्यवस्था की सुभेद्यता को उजागर किया।
  - कोवडि-19 महामारी के दो वर्ष बाद भी अर्थव्यवस्थाओं पर इसके प्रतिकूल प्रभाव से उबरना बहुत चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
  - हालाँकि भारत ने नरियात में काफी लचीलापन दर्शाया है और रकिॉर्ड स्तर पर उच्च वकिस दर हासलि की है। भारत वतित वर्ष 2021-22 की शुरुआत से नरियात में सकारात्मक आँकड़े दर्ज कर रहा है और दसिंबर 2021 में भारत ने 37 बलियिन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक नरियात किया है, जो दसिंबर 2020 की तुलना में 37% अधिक है।



increasing 197.03%.

■ नरियात बढ़ाने का सुझाव:

- नरियात अवसंरचना और बाज़ार संकेंद्रण: बेहतर नरियात प्रदर्शन हेतु विश्वसनीय एवं कुशल नरियात बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश करना आवश्यक है, जो लागत में कमी और नरियात दक्षता में सुधार करने में मदद करेगा।
- नरियात विविधीकरण की आवश्यकता: यह नरियात क्षेत्र में स्थिरता एवं विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- नरियात बुनियादी ढाँचे के विकास, उद्योग-अकादमिक संबंधों को मज़बूत करने और नरियात में चुनौतियों का समाधान करने हेतु आर्थिक कूटनीतिके लिये राज्य-स्तरीय जुड़ाव जैसी प्रमुख रणनीतियों पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।
- नरियात को बढ़ावा देने में नज़ी क्षेत्र भी अहम भूमिका निभा सकता है।

## वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: फरवरी 2006 में लागू हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2010)

1. अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास।
2. विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना।
3. केवल सेवाओं के नरियात को बढ़ावा देना।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से इस अधिनियम का/के उद्देश्य है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

स्रोत: पी.आई.बी.